

सासाहिक

न्यूज क्राइम फाइल

ग्वालियर, शिंडे, मुरैना, छत्पुर, खागड़, बिहिशा, रायसेन, क्षिवनी, जबलपुर, शीला, झत्ना, होशगंगाबाद, हरद्वा एवं झंडौर में प्रस्तावित।

मूल्य- 02 रुपये

बहनों को रक्षाबंधन में मिलेगा 250 रुपये का शुगुन

दीपावली के बाद बहनों को हर महीने देंगे 1500 रुपए : मुख्यमंत्री



उदय प्रताप सिंह चौहान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंगरौली प्रदेश का सीमावर्ती, खनिज सम्पन्न और सर्वप्रिय जिला है। सिंगरौली को शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज की सौगत मिलने वाली है। अगले साल से यहां पढ़-लिखकर डॉक्टर निकलेंगे। आज प्रदेशभर के 94 हजार 234 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि ट्रांसफर की गई है। इसमें 60 प्रतिशत छात्राएं और 40 प्रतिशत छात्र शामिल हैं। राज्य सरकार जनजातीय अंचल में सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। बीते 2 साल में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 15 हजार से अधिक स्कूटी बांटी गई हैं। हमारी सरकार सबके चतुर्दिक विकास के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को सिंगरौली जिले के सरई गांव में महिला सशक्तिकरण तथा जनजातीय गौरव सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कुछ दिनों बाद 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, इस दिन प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज, हॉस्टल सहित बच्चों की सुविधा से जुड़े निर्माण कार्यों का एक साथ लोकार्पण होगा। शासकीय स्कूलों के बच्चों को साइकिल, ड्रेस और किताबों का वितरण भी किया जाएगा। भागवत गीता से मध्यप्रदेश का संबंध है। वृद्धावन ग्राम बनाकर भगवान श्रीकृष्ण-सुदामा की मित्रता को जीवंत करना है। बच्चे पढ़ाई करके कहीं भी जाएं, पर अपने गरीब मित्र को न भूलें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विपक्षी दल की सरकार के समय प्रदेश में बेटे-बेटियों के लिंगानुपात में बढ़ा अंतर था। हमारी सरकार में लाड़ली बेटी जन्म से ही लखपति हो, इसकी शुरुआत मध्यप्रदेश से हुई। बेटियाँ जब 18 वर्ष की उम्र पूरी करेंगी, तो सरकार की ओर से उन्हें एक-एक लाख रुपए से अधिक राशि दी जाएगी। राज्य सरकार लाड़ली बहनों और स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को और अधिक सशक्त करने के लिए कार्य कर रही है। पहले प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 11 हजार थी, लेकिन अब हमारी सरकार के प्रयासों से यह 1 लाख 52 हजार रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन से पहले सभी पात्र बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि शुगुन के रूप में भेजी जाएगी। दीपावली के बाद हम प्रदेश की सभी लाड़ली बहनों को हर माह 1500 रुपए महीना देंगे। उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों के हाथ में पैसा रहे तो घर ठीक से चलता है। मुख्यमंत्री

ने कहा कि आदिवासियों के सम्मान और गरीबों के कल्याण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमने रानी दुर्गावाती और राजा भभूत सिंह की स्मृति में कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की है। श्रीअन्न खरीदने पर किसानों को एक हजार रुपये प्रति किंटल अतिरिक्त राशि दी जा रही है। किसानों से 26 सौ रुपये प्रति किंटल में गेंहू की खरीद की गई जो देश में सर्वाधिक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने 27 हजार करोड़ से अधिक की बजट राशि महिलाओं को समर्पित की है। लाड़ली बहना योजना के लिए 18 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान रखा है। आज प्रदेश में 51 लाख से अधिक लाड़ली बेटियां पंजीकृत हैं इनमें से 12 लाख 99 हजार बेटियों को 672 करोड़ की छात्रवृत्ति दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 62 लाख बहनों के 5 लाख स्व-सहायता समूहों को राज्य सरकार सशक्त करने के लिए धनराशि दे रही है। प्रदेश की बहनों को नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बहनों को 33 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका हक दिलाने में हमने कोई कमी नहीं रखी है। हमारी सरकार में प्रदेश के 4 जिलों में महिला अधिकारी जिला कलेक्टर का दायित्व संभाल रही हैं। राज्य सरकार गरीब से गरीब के जीवन में सबेरा लाने का कार्य कर रही है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वर्चित पात्र हितग्राहियों की पहचान के लिए नए सिरे से सर्वे शुरू किया गया है।

संपत्ति की रजिस्ट्री में एक प्रतिशत की छूट देने से आज 45 प्रतिशत रजिस्ट्री बहनों के नाम पर हो रही हैं। यह हमारी पहल का ही सुखद परिणाम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय समुदाय के लिए राज्य सरकार नेक-नीयत और विशेष भावना से कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। सिंगरौली की कुल आबादी में 39 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है, इनमें से 5 लाख को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार की भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंद्या मामा आर्थिक कल्याण योजना से जनजातीय वर्ग को बड़ी मदद मिली है। प्रधानमंत्री जन-मन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का लाभ भी जनजातीय वर्ग को दिया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें फसलों का समुचित मूल्य देने के लिए संकल्पित है।



भोपाल में प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष का हुआ स्वागत

हेमंत खंडेलवाल बोले-कार्यकर्ताओं की बदौलत ही सबकुछ हैं

न्यूज क्राइम फाइल

यह कहना है प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का। वे शुक्रवार को रविंद्र भवन में भाजपा भोपाल आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस मंच पर 12 शेर ही बैठे हैं। जिन्होंने पार्टी को इतनी ऊँचाई पर लाने का काम किया है। पिछले चुनाव में नगर निगम और नगरपालिकाओं के सारे टिकट उन्होंने ही बांटे थे लेकिन उन्हें ही टिकट दिया जिसे कार्यकर्ताओं और विधायकों ने चाहा।

मंत्री सारंग बोले- खंडेलवाल की राजनीतिक सोच बड़ी

कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हेमंत खंडेलवाल शरीर से छोटे जरूर हैं पर राजनीतिक सोच बड़ी है। संगठन और सरकार प्रदेश के विकास को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अगले चुनाव में भोपाल मध्य और भोपाल उत्तर में भी बीजेपी की जीत का संकल्प लेकर जाना है। यही वास्तविक स्वागत होगा।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा-

नए अध्यक्ष संगठन के मुखिया के रूप में जो तय करेंगे वह सभी पूरा करेंगे। सहज सरल कार्यकर्ता को जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है इससे हम सब गौरवान्वित हैं। नए अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करना है, इसलिए सभी को इसका ध्यान रखना है।



जैसे बाहर से, वैसे अंदर से हैं नए अध्यक्ष

पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने कहा कि नए अध्यक्ष जैसे बाहर से हैं, वैसे ही अंदर से सहज और सरल हैं। वहीं पूर्व मंत्री उमाशंकर गुसा ने कहा कि हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कार्यक्रम में मौजूद हर कार्यकर्ता अपने को प्रदेश अध्यक्ष मानता है। यही उनकी सहजता है। खंडेलवाल हमेशा पीछे रहकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और उनके नेतृत्व में संगठन मजबूत होगा। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुसा ने कहा कि हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कार्यक्रम में मौजूद हर कार्यकर्ता अपने को प्रदेश अध्यक्ष मानता है। यही उनकी सहजता है। खंडेलवाल हमेशा पीछे

रहकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और उनके नेतृत्व में संगठन मजबूत होगा।

भाजपा दफ्तर में कर्मचारियों से मिले प्रदेश अध्यक्ष

शुक्रवार को ही प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ प्रदेश कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से परिचय प्राप्त की। इस दौरान हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि आप सभी कर्मचारी पार्टी की एक अहम कड़ी हैं। आप केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि इस विचार परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी संस्था से जुड़ता है, तो वह उस संस्था की संस्कृति, विचार और कार्यपद्धति का सहभागी बन जाता है। सभी कर्मचारियों के लिए मेडिकल

क्लेम और बीमा की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारियों के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो पार्टी उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए हरसंभव आर्थिक मदद प्रदान करेगी। यदि किसी को बैंक लोन की आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं गारंटी देने को तैयार हूं, ताकि आपके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बन सके। हर सदस्य का परिवार सुरक्षित एवं संरक्षित भाव से रहे हम इसका सदैव ध्यान रखेंगे। शीघ्र ही पार्टी कार्यालय परिसर में कम शुल्क पर भोजन व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी।

हितानंद ने कहा- परिचय आपस में बढ़ाता है प्रेम

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि 'बिनु प्रतीत होइ न प्रीति' अर्थात् बिना परिचय के प्रेम और विश्वास नहीं होता। उन्होंने कहा कि यही उद्देश्य लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रत्येक सदस्य से व्यक्तिगत परिचय प्राप्त किया है, ताकि पारिवारिक भाव और आपसी विश्वास को और सशक्त किया जा सके। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉ. राघवेंद्र शर्मा ने सभी कर्मचारियों का परिचय प्रदेश अध्यक्ष से कराया। प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी अशीष ऊषा अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार एवं प्रदीप त्रिपाठी सहित पार्टी कार्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

प्रोत्साहन



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

खुद को जज बताकर एक महीने बुजुर्ग का किया परेशान



न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल के अरेरा कॉलोनी में रहने वाले 68 वर्षीय बुजुर्ग के मोबाइल पर दिसंबर से लगातार अनजान नंबर से कॉल और मैसेज आने लगे। कॉल करने वाला खुद को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बता रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसके वॉट्सऐप प्रोफाइल पर सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जस्टिस की फोटो लगी थी। डीपी

देखकर बुजुर्ग भ्रमित हो गए और कुछ दिन तक बात करते रहे। धीरे-धीरे कॉल की टाइमिंग रात 12 बजे के बाद की होने लगी। मैसेजों की भाषा और विषय भी अजीब थे। थककर बुजुर्ग ने यह बात बेटे को बताई। बेटे ने हबीबांज थाने में शिकायती आवेदन दिया। जांच के बाद अब अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

बेटी का नाम लेकर बातचीत की शुरुआत की

24 दिसंबर 2024 को बुजुर्ग के मोबाइल पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बोल रहा हूं, आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ पढ़ती है। इसके बाद लगातार वॉट्सऐप मैसेज भेजे जाने लगे। डीपी में सुप्रीम कोर्ट के जज की फोटो देखकर बुजुर्ग ने शुरुआत में विश्वास कर लिया। कुछ दिनों तक बातचीत चलती रही, लेकिन फिर आरोपी की बातों में न कोई तर्क था और न उद्देश्य।



कब्रिस्तान जमीन पर गोशाला निर्माण को लेकर विवाद

जमीअत उलमा और स्थानीय लोगों निर्माण रुकवाने पहुंचे, पुलिस-प्रशासन भी मौके पर

न्यूज़ क्राइम फाइल

भोपाल में कोलार इलाके के अकबरपुर बंजारी स्थित कब्रिस्तान-गोशाला निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग और जमीअत उलमा कोलार रोड की टीम मौके पर पहुंची और वहां हो रहे निर्माण कार्य का विरोध किया। मामला बढ़ता देख पुलिस और एसडीएम मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने जांच पूरी होने तक किसी भी निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आश्वासन दिया है। जमीअत उलमा जिला भोपाल के अध्यक्ष हाफिज इस्माइल बैग के निर्देश पर तहसील कोलार के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद हनीफ खान की अगुआई में जमीअत की टीम अकबरपुर कब्रिस्तान पहुंची। उनका कहना था कि यहां वक्फ बोर्ड की जमीन पर बिना अनुमति के गोशाला का निर्माण कराया जा रहा है।

इलाके के लोगों ने भी जाताया विरोध जमीअत की अपील पर स्थानीय मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी संख्या में कब्रिस्तान पहुंचे और अवैध निर्माण का विरोध किया। मौके पर तनाव की स्थिति बन गई थी लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। बता दें कि कब्रिस्तान के केयरटेकर शेख मतीन ने आरोप लगाया था कि यह जमीन वक्फ बोर्ड रजिस्ट्रेशन क्रमांक 766 के तहत पंजीकृत है। इसके बावजूद कांग्रेस नेता अश्विनी श्रीवास्तव और उनके सहयोगी यहां जबरन गोशाला बना रहे हैं।



एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा

मौके पर पहुंचे एसडीएम कोलार आदित्य जैन पहुंचे, इस पर एसडीएम ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने तक कोई निर्माण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए थे, हमने उन्हें समझाइश दी और वह रवाना हुए। इस मामले

में हम जांच कमेटी गठित करेंगे, फिलहाल निर्माण कार्य रुकवा दिया है। बता दें कि इस मामले में 21 जून को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और टेंट लगाकर निर्माण की तैयारी शुरू की। इसके बाद 23 जून को अश्विनी श्रीवास्तव ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की मौजूदगी में भूमिपूजन किया गया था।

पुलिस ने कहा— आदेश दिखाइए, नहीं तो हटिए

इस दौरान यहां भारी पुलिस बल भी तैनात था, एक वीडियो में पुलिस विवाद के दौरान मौलाना हनीफ ने पुलिस से कहा कि हमने थाने और कलेक्टर को शिकायत दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर पुलिस ने कहा कि निर्माण रुकवाने का कोर्ट का आदेश दिखाइए, अन्यथा यहां से हटिए।

पहले भी हो चुका है प्रदर्शन

इस मामले में ऑल ईंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने हाल ही में को वक्फ बोर्ड कार्यालय के सामने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांकेतिक कब्रें बनाई, कफन ओढ़े लोग मुर्दा बनकर जमीन पर लेटे और सवाल पूछा— अगर कब्रिस्तान पर मौल और गोशालाएं बनेंगी, तो हम अपने मरे हुओं को कहां दफनाएंगे? प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समिति के संरक्षक शमसुल हसन ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कभी 189 पंजीकृत कब्रिस्तान थे, लेकिन आज सिर्फ 22 बचे हैं। कब्रिस्तान की जमीनों पर योजनाबद्ध तरीके से कब्जे हो रहे हैं।

वक्फ का आरोप- कांग्रेस नेता कब्रिस्तान पर गोशाला बना रहे

भोपाल में कोलार क्षेत्र के अकबरपुर बंजारी में कब्रिस्तान की जमीन पर गोशाला बनाई जा रही है। कब्रिस्तान के केयरटेकर शेख मतीन ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि इस जमीन पर वक्फ बोर्ड का रजिस्टर्ड कब्रिस्तान की है, जिस पर कांग्रेस नेता अश्विनी श्रीवास्तव कब्जा कर गोशाला बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

भोपाल में हमीदिया अस्पताल की दीवार पर पोता हरा रंग

अतिक्रमण कर लगाया धार्मिक झंडा, जूड़ा ने की थाने में शिकायत

न्यूज़ क्राइम फाइल

भोपाल में हमीदिया अस्पताल परिसर की बाउंड्रीवॉल पर कुछ लोगों ने हरे रंग से पेंट करने के बाद वहां झंडा लगा दिया। शुक्रवार को अस्पताल के ब्लॉक-2 के पीछे इमरजेंसी के पास कुछ बाहरी लोग धार्मिक गतिविधियां करने लगे। इसकी जब अस्पताल के जूनियर डॉक्टर और कर्मचारियों को जानकारी लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कहासुनी और विवाद की स्थिति बन गई। मामला बढ़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इधर, जूनियर डॉक्टरों के संगठन जूड़ा ने इस पूरे मामले की शिकायत की है। जूड़ा के अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता ने कहा कि हमने पुलिस थाना और अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की है।

पुराना है अतिक्रमण का विवाद
यह कोई पहला मामला नहीं है जब



हमीदिया अस्पताल परिसर में धार्मिक अतिक्रमण हुआ है। पिछले साल भी लाइब्रेरी के पास बनी एक मजार को बढ़ाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। उस समय सिर्फ एसडीएम ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर अतिक्रमण को चिह्नित किया था। इसके बाद

जिला प्रशासन, गांधी मेडिकल कॉलेज, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और अन्य विभागों की संयुक्त बैठक कर कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

धर्मस्थलों की संख्या में इजाफा

लगभग एक दशक पहले तक हमीदिया अस्पताल परिसर में केवल ऐतिहासिक ढाई सीढ़ी मस्जिद, एक छोटा हनुमान मंदिर, एक मस्जिद और दो छोटी मजारें थीं। लेकिन, बीते दस सालों में यहां तीन नए मंदिर बन गए हैं। आरोप है कि बाहरी लोगों ने पुराने मंदिर में समिति बनाकर दूसरे मंदिर भी खड़े कर दिए हैं। उधर, एडमिन ब्लॉक के पास स्थित एक छोटी मजार को अतिक्रमण कर बड़ी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। यह सब कुछ अस्पताल प्रशासन और संबंधित विभागों की मिलीभगत या लापरवाही के चलते होता रहा है।

कर्नाटक में कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाली गलती दोहरा रही है

कर्नाटक में कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज की थी। यह जीत केवल भाजपा को सत्ता से हटाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके साथ ही कांग्रेस ने यह संदेश भी दिया था कि यदि पार्टी एकजुट और ठोस नेतृत्व के साथ मैदान में उतरे तो वह भाजपा को धेर सकती है। लेकिन अब, कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और लगातार सार्वजनिक रूप से सामने आने वाले मतभेदों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कांग्रेस यहां पर वही गलती दोहरा रही है जो उसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में की थी? हम आपको याद दिला दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का विवाद कांग्रेस के लिए दीर्घकालिक सिरदर्द बना रहा था। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच सत्ता-साझेदारी को लेकर विवाद लगातार सामने आता रहा था। ऐसा ही वाकया मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच देखने को मिला था। ज्योतिरादित्य भाजपा में चले गये थे जिससे कमलनाथ की सरकार बीच में ही गिर गयी थी। तीनों ही राज्यों में मतभेद पार्टी मंच के बजाय मीडिया में उछलते रहे, जिससे भाजपा को सत्ता में आने का मौका मिल गया। इसी तरह कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है कि आलाकमान द्वारा समय रहते निर्णयक कदम नहीं उठाने के कारण टकराव बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की जोरदार जीत के बाद से ही यह स्पष्ट था कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। समझौते के तहत सिद्धारमैया को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन शिवकुमार खेमा इसे अंदर ही अंदर चुनौती दे रहा है। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो चाहे प्रशासनिक निर्णयों की बात हो या फिर रणनीतिक घोषणाओं की बात हो, सभी मामलों में दोनों नेताओं के बीच मतभेद लगातार उजागर होते रहते हैं। इसके अलावा, कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी खुलेआम एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। डीके शिवकुमार के



समर्थक अक्सर उन्हें भावी मुख्यमंत्री कहकर प्रचारित करते हैं जो सिद्धार्थमैया समर्थकों को असहज करता है और इसके चलते दोनों ओर से बयानबाजी शुरू हो जाती है। हम आपको बता दें कि देश में सिर्फ तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और देखने में आ रहा है कि तीनों जगह पार्टी में कलह है। कर्नाटक के साथ ही हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी कांग्रेस नेता आपस में भिड़े हुए हैं लेकिन कर्नाटक की कलह कुछ ज्यादा ही उजागर हो रही है। यही नहीं, कर्नाटक के विवाद को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा हाईकमान पर टालना दर्शाता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है और सब कुछ ऊपर से ही मैनेज हो रहा है, तभी इस प्रकार का टकराव बना हुआ है। देखा जाये तो कांग्रेस इस समय देश में मग्न

विपक्षी पार्टी है इसलिए सवाल उठता है कि जब वह अपना घर ही नहीं संभाल पा रही तो देश में मजबूत विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पायेगी ? कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों को भी एकजुट रख पाने में विफल रही है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि केरल और हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सरकार में आना तय माना जा रहा था लेकिन अपने ही नेताओं के आपसी झगड़ों की बदौलत पार्टी सत्ता से बहुत दूर रह गयी थी।

इससे साबित होता है कि कांग्रेस को हमेशा अपनों ने ही लूटा है लेकिन फिर भी पार्टी गलतियों से सीख लेने को तैयार नहीं है। उधर, कर्नाटक में कांग्रेस के दोनों धुरंधर नेताओं के समीकरणों पर गौर करें तो आपको बता दें कि

अत्यंत पिछड़े कुरबा समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बड़े जनाधार वाले नेता हैं। वह सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं और उन्हें पता है कि चुनावों में भाजपा के जातिगत समीकरणों को कैसे बिगाड़ना है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आर्थिक-सामाजिक रूप से संपन्न वोक्कालिग समुदाय से आते हैं। वह पुराने कांग्रेसी हैं, गांधी परिवार के विश्वस्त हैं और धनबल, बाहुबल के खिलाड़ी हैं। कई विधायक भी उनके साथ हैं लेकिन हाईकमान हर बार सिद्धारमैया के सिर पर हाथ रख देता है इसलिए उन्होंने हाल ही में कहा भी है कि मेरे पास समर्थन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। कर्नाटक में एक बात और देखने को मिल रही है कि यहां कांग्रेस की गलतियों की वजह से मामला पेचीदा होता जा रहा है।

दरअसल असंतुष्टों पर ना तो कांग्रेस कोई कार्रवाई कर रही है ना ही उन्हें राजनीतिक रूप से कहीं समायोजित कर रही है। ऐसे में विधायकों का धैर्य जवाब दे रहा है। कर्नाटक में स्थिति यह है कि सत्तारुद्ध दल का हर विधायक मुख्यमंत्री बनना चाहता है इसलिए भी पार्टी के लिए हालात को सभालना मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा, कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी योजनाएं चुनाव जिताने में तो सहायक रहीं, लेकिन अब उनके क्रियान्वयन में वित्तीय संकट और प्रशासनिक गड़बड़ियाँ भी सामने आ रही हैं। सत्तारुद्ध दल के विधायक ही कह रहे हैं कि हमें हमारे क्षेत्र के विकास के लिए फंड नहीं मिल रहा। इस सब स्थिति के बीच भाजपा चुपचाप कर्नाटक में खुद को मजबूत करने और सामाजिक समीकरणों को सहेजने में लगी है ताकि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपना प्रदर्शन सुधारा जा सके। बहरहाल, कर्नाटक की राजनीति में अक्सर नये नाटक होते रहते हैं इसलिए देखना होगा कि फिलहाल विधायकों से बातचीत के बाद कांग्रेस ने राज्य में %ऑल इज वेल% का जो दावा किया है वह स्थिति कब तक बनी रहती है।

दलाई लामा के चयन पर चीन का साजिशपूर्ण हस्तक्षेप

तिब्बत के आध्यात्मिक नेता एवं वर्तमान 14वें दलाई लामा, तेनजिन ग्यात्सो की उत्तराधिकार प्रक्रिया न केवल बौद्ध धर्म और तिब्बत की संस्कृति से जुड़ा विषय है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय

राजनीति, मानवाधिकार और भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। चीन द्वारा इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, बल्कि यह वैश्विक जनमत की भी अवहेलना है। इन स्थितियों में उत्तराधिकार के मसले पर भारत की भूमिका एक निर्णयक मार्गदर्शक के रूप में उभरती है और इसे दृष्टि में रखते हुए भारत ने दलाई लामा का पक्ष लिया है। ऐसा करने में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हैं। भारत शुरू से तिब्बतियों के अधिकार, उनके हितों और उनकी परंपराओं व मूल्यों के समर्थन में खड़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान चीन के लिए यह संदेश भी है कि इस संवेदनशील मसले पर उसकी मनमानी नहीं चलेगी। चीन, दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, यह दावा करते हुए कि यह धार्मिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि, दलाई लामा और तिब्बती समुदाय का कहना है कि यह अधिकार केवल उनके पास है और चीन का हस्तक्षेप धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। चीन, 'स्वर्ण कलश' प्रणाली का उपयोग करके अपने पसंदीदा अमीदवार को स्थापित करना चाहता है। चीन का कहना है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार उसे 'स्वर्ण कलश' प्रणाली के माध्यम से है, जो 1793 में किंग राजवंश के समय से चली आ रही है। इस प्रणाली में, संभावित उत्तराधिकारियों के नाम एक कलश में डाले जाते हैं और फिर एक नाम निकाला जाता है। दलाई लामा केवल तिब्बत के धार्मिक नेता नहीं हैं, वे तिब्बती अस्मिता, स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान के प्रतीक हैं। वर्तमान 14वें दलाई लामा, तेनजिन ग्यात्सो, 1959 में चीन की दमनकारी नीतियों के कारण तिब्बत छोड़कर भारत आए और धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना हुई। भारत ने न केवल उन्हें शरण दी, बल्कि एक शातिष्ठी संघर्ष के पथप्रदर्शक के रूप में वैश्विक स्तर पर उनके विचारों को मंच भी प्रदान किया। वर्तमान दलाई लामा ने इस पद के लिए अगले शख्स को चुनने की सारी जिम्मेदारी गाड़ेरंग ट्रस्ट को दे दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में किसी और को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उनका इशारा चीन की ओर था। रिजिजू ने भी इस बात का समर्थन किया है। वहीं, चीन ने इस मसले में साजिशपूर्ण हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि उत्तराधिकारी का चयन चीनी मान्यताओं के अनुसार और पेइंचिंग की मंजूरी से होना चाहिए। चीन दलाई लामा की उत्तराधिकार प्रक्रिया पर नियंत्रण चाहता है ताकि तिब्बती जनता को अपने ही धार्मिक नेता से अलग किया जा सके। 2007 में चीनी सरकार ने एक 'धार्मिक मामलों पर नियंत्रण कानून' लागू किया जिसके अंतर्गत दलाई लामा जैसे धार्मिक नेताओं की नियुक्ति भी राज्य की अनुमति से ही संभव बताई गई। यह न केवल बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है, बल्कि यह तिब्बती जनता की आस्था और पहचान का गला घोटने जैसा है।



बागेश्वरधाम में अचानक गिरा पंडाल, भागने लगे लोग

धीरेंद्र शास्त्री बोले- धाम देगा पीड़ित परिवार को एक दिन की दान राशि



न्यूज क्राइम फाइल

तेज बारिश हो रही थी। हम चाय बना रहे थे। एक दम से पंडाल गिर गया। लोग यहां-वहां भागने लगे। पंडाल के ऊपर पानी भर गया था। हम लोगों के पास गए। तब उन्होंने कहा कि किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन बाद में पता चला कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। ये कहना है चाय की दुकान चलाने वाले रुजू का, जिसके सामने गुरुवार सुबह बागेश्वरधाम परिसर में टेंट गिर गया था। हादसे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्यामलाल कौशल की मौत हो गई थी, जबकि 12 लोग घायल हुए थे। हादसे के बाद दैनिक भास्कर की टीम बागेश्वरधाम पहुंची। टीम ने यहां की व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु और दुकानदारों से बात की। वहां शुक्रवार को धीरेंद्र शास्त्री ने मृतक के परिवार को धाम

में आई तीन जुलाई की पूरी चढ़ोत्तरी यानी दान राशि देने की बात कही।

पंडाल में रात में होती है चोरियां
प्रयागराज से बागेश्वरधाम पहुंचे श्रद्धालु आनंद मिश्रा ने बताया, यहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उनके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब सबके लिए तो बीआईपी इंजाम कर नहीं सकते। यहां काफी लोग पंडाल में रुकते हैं, लेकिन यहां चोरियां में बहुत होती हैं। इस कारण कुछ लोग दुकानों और ढाबों पर ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं। जो सक्षम हैं वो होटल में रुक जाते हैं।

मृतक के परिवार को देंगे एक दिन की चढ़ोत्तरी

3 जुलाई को बागेश्वरधाम के टेंट गिरने से हुई दुर्घटना में अयोध्या के निवासी श्यामा लाल कौशल की मौत हो गई थी। अब उनके परिवार के लिए बागेश्वरधाम के धीरेंद्र शास्त्री ने घोषणा की है कि 3

जुलाई को आई पूरी दक्षिणा दी जाएगी। बागेश्वर महाराज ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर मंच से इसकी घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के जन्मदिन पर बहुत ज्यादा उल्लास नहीं है। कल (गुरुवार) जो प्राकृतिक घटना हुई, हमने ऐसा विचार किया कि कल जो चढ़ोत्तरी मिली, उस पूरी चढ़ोत्तरी को मृतक परिवार को साँपा जाए ताकि उनका जीवन चल सके और तो हम कुछ दे नहीं सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि लौटा नहीं सकते। भगवान से प्रार्थना करें कि सबको सुरक्षित और स्वस्थ रखे। आप सब प्रसन्न रहें।

प्रशासन सतर्क, संगीत कार्यक्रम रद्द

बागेश्वरधाम में एकाएक हुए हादसे के बाद प्रशासन भी चौकन्ना हो गया हैं, जिसके चलते धाम पर लगे अर्टिफिशियल टेंट को हटाया गया और टेंटों की मजबूती को चेक किया गया। बारिश में सुरक्षित स्थान पर रहने की एडवाइजरी भी जारी की है। साथ ही धीरेंद्र शास्त्री के जन्मोत्सव के दौरान होने वाले संगीत कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया। यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और भंडारे में प्रसाद बांटा जाएगा।

डेढ़ लाखों के लिए बना रहा भोजन

बागेश्वरधाम में लगभग 1:50 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था जा रही है। मटर पनीर की सब्जी के अलावा कहुं की सब्जी, छोले की सब्जी भी मिलेगी। वहां पुलाव, सूजी का हलवा, खीर जैसे व्यंजन भी हैं। पूँडी-सब्जी के साथ-साथ मिठाई के भी बंदोबस्त किया गया है।

विदिशा में 12 झोलाछाप डॉक्टरों की विलनिक सील



न्यूज क्राइम फाइल

विदिशा जिले के लटेरी में एक मासूम की संदिग्ध हालत में मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिलेभर में झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की है। शुक्रवार को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 12 फर्जी डॉक्टरों की क्लीनिक और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। शहर के करेया खेड़ा रोड स्थित महाकाल क्लीनिक, पीतल मिल चौराहा स्थित श्री सेवा मेडिकल और निलेश जैन की क्लीनिक, वकील साहब कॉलोनी में सार्व क्लीनिक को सील किया गया। वहां, निलेश में गायत्री क्लीनिक और शर्मा क्लीनिक और सिरोंज में हाजीपुर में कुशवाहा क्लीनिक (हरिओम कुशवाहा) को सील किया गया। ग्राम हांसुआ में कृष्णा क्लीनिक और विश्वकर्मा क्लीनिक पर भी कार्रवाई हुई। गंजबासौदा के स्वरूप नगर में साई दवाखाना, लटेरी के मलनिया रोड पर अधिक नामदेव प्राइवेट क्लीनिक और कृष्णा पैथोलॉजी को भी सील किया गया। जिले के कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने बच्चे की मौत को गंभीरता से लेते हुए झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुनीत माहेश्वरी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। टीम में बीएमओ निलेश डॉ. नीतू सिंह राय, बीएमओ सिरोंज डॉ. विकास बघेल, बीएमओ विदिशा डॉ. हेमंत कुमार पंचोली, बीएमओ गंजबासौदा डॉ. प्रमेन्द्र तिवारी और बीएमओ लटेरी डॉ. अभिषेक उपाध्याय शामिल रहे।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा- आगे भी चलेगा अधियान

स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि यह अभियान यहां नहीं रुकेगा। अवैध तरीके से इलाज कर रहे डॉक्टरों, बिना लाइसेंस क्लीनिक और बिना योग्यता वाले मेडिकल स्टोर के खिलाफ अब लगातार कार्रवाई की जाएगी।

पत्रकार बनने का सुनहरा अवसर

अगर आपके अंदर लिखने का कौशल है और पत्रकारिता में रुचि है, तो 'न्यूज क्राइम फाइल' को आपकी तलाश है। 'न्यूज क्राइम फाइल' से जुड़ कर आप हर माह दस हजार रुपये तक कमा सकते हैं। 'न्यूज क्राइम फाइल' भोपाल, ग्वालियर, सतना, सागर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और नीमच में व्यूरो ऑफिस खोलने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार तत्काल हमें अपना बॉयोडाटा मेल करें या व्हाट्सअप करें।

उदय प्रताप सिंह चौहान (संपादक) 07223003441

website: www.newscrimefile.com

email: newscrimefile@yahoo.com



सैफ की पुश्तैनी संपत्ति विवाद, नए सिरे से होगी सुनवाई: एमपी हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को किया निरस्त

न्यूज क्राइम फाइल

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने भोपाल स्थित सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति के विवाद पर ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट के 14 फरवरी 2000 को पारित आदेश को दोषपूर्ण पाते हुए निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि ट्रायल कोर्ट एक साल की समय सीमा के अंदर प्रकरण का पटाक्षेप करे। यह आदेश हाईकोर्ट ने भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की संपत्ति को लेकर चल रहे उत्तराधिकार विवाद को लेकर सुनाया। अपील नवाब हमीदुल्लाह खान के वंशज बेगम सुरेया, नवाबजादी कमरताज राबिया सुल्तान और अन्य की ओर से दायर की गई थी। इस प्रकरण में मशहूर क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी, उनकी पत्नी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, पुत्र सैफ अली खान, बेटियां सबा सुल्तान, सोहा अली खान को पक्षकार बनाया गया था। इस मामले में यसीर और फैजा सुल्तान का दावा था कि नवाब की निजी संपत्ति पर सभी वैध वारिसान का अधिकार है।

अरबों की संपत्ति का है मामला

सैफ अली खान से जुड़ी संपत्ति विवाद की बात करें तो 25 साल पहले बेगम सुरेया,



नवाबजादी कमर ताज राबिया सुल्तान, नवाब मेहर ताज साजिदा सुल्तान और बेगम मेहर ताज नवाब साजिदा सुल्तान ने साल 2000 में हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। ये मामला अरबों की संपत्ति का है, जिसमें हजारों एकड़ की जमीन समेत अहमदाबाद पैलेस भी शामिल है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कोर्ट में सैफ के परिवार की चुनौतियां आने वाले एक साल के लिए बढ़ गई हैं।

कैसे भोपाल रियासत में सैफ का हक ?
दरअसल, नवाब हाफिज सर हमीदुल्लाह खान

का पूरा नाम सिकंदर सौलत इफतेखारल उल मुल्क बहादुर हमीदुल्लाह खान था। ये भोपाल के अंतिम नवाब थे। जिनका 1956 में मध्य प्रदेश राज्य में विलय हो गया था। इन्होंने दो शादी की थी। इनकी मौत के बाद उनकी बड़ी बेगम की बेटी साजिदा को भारत सरकार ने 1961 में कानूनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। साजिदा, सैफ अली खान की परदादी थीं। इनकी शादी पटौदी रियासत के नवाब इफतेखार अली खान से हुई थी। उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी और फिर उनके बेटे सैफ को इस संपत्ति का वारिस माना गया।

इंस्टाग्राम पर लाइव आकर युवक ने किया सुसाइड

न्यूज क्राइम फाइल

सागर में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले उसने लाइव आकर कहा कि कभी कोई किसी को प्यार न करें लाइफ में, जो किसी को टाइम न दे सके। मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, आप लोग सब लाइव देखो। इसके बाद उसने फांसी लगा ली। घटना सागर के सानौरा थाना क्षेत्र के शाहपुर में 22 जून की है। दीपराज अहिरवार (20) ने घर में आत्महत्या कर ली थी। शुक्रवार को इसका वीडियो सामने आया। परिजन ने कहा कि छतरपुर की यूट्यूबर युवती ने उससे बात करनी बंद कर दी थी। इससे वह परेशान था। युवक के परिजन ने थाने पहुंचकर शिकायत कर बयान दर्ज कराए हैं। उन्होंने छतरपुर की रहने वाली एक यूट्यूबर युवती पर बेटे को परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस वीडियो और परिवार वालों के आरोपों पर जांच कर रही है। मृतक का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह इंस्टाग्राम पर लाइव सुसाइड करते हुए नजर आया है। वीडियो में वह कह रहा है कि मैं जीना नहीं चाहता हूं यार, मैं फांसी लगाने वाला हूं।

सौजन्य भेट



एक जुलाई को सरल एवं सहज व्यक्तित्व के धनी उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के भोपाल रियास पर न्यूज क्राइम फाइल के संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार उदय प्रताप सिंह ने उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को जन्मदिवस शुभकामनाएं दी।

मैहर में नायब तहसीलदार को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश



न्यूज क्राइम फाइल

मैहर जिले के कुबरी गांव में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे नायब तहसीलदार रोशन रावत पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश की गई। गर्नीमत है कि वह बाल-बाल बच गए। घटना के समय 40 से 50 ग्रामीण मौजूद थे। मामले में रामनगर थाने में शिकायत की जा रही है। नायब तहसीलदार रोशन रावत ने बताया कि कुबरी गांव में मुन्नी बाई रजक का रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। गांव में सीमांकन करने जा रहे थे, तभी रास्ते में रेत से भरा ट्रैक्टर आगे जा रहा था। उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर चालक नहीं रुका, तभी सामने से आ रही गाड़ी की वजह से ट्रैक्टर रुक गया। इसके बाद मैं गाड़ी से उस लड़के का पिता रवेंद्र उर्फ नेपाली आया और ट्रैक्टर स्टार्ट कर हम लोगों पर चढ़ाने का प्रयास किया। हम लोगों ने भाग कर जान बचाई। इस दौरान कुछ लोग गिर गए, जिन्हें चोट लगी है। आरोपी तेज रफतार में ट्रैक्टर लेकर भाग गया। इसके बाद मैंने अमरपाटन एसडीम आरती सिंह एवं रामनगर थाना प्रभारी को सूचना दी। आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है।



पाकिस्तान हॉकी एशिया कप के लिए भारत आएगा

खेल मंत्रालय खोला- हम किसी को नहीं रोकेंगे; पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों की एंट्री बैन थी

न्यूज़ क्राइम फाइल

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति के बावजूद हॉकी एशिया कप और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम को भारत आने से नहीं रोका जाएगा। खेल मंत्रालय के सूत्र ने न्यूज़ एंजेंसी से कहा कि हम द्विपक्षीय सीरीज के खिलाफ हैं, लेकिन टूर्नामेंट के लिए हम किसी भी टीम को भारत आने से नहीं रोकेंगे। मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, %इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में टीमें तनाव के बावजूद हिस्सा लेती हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बावजूद टूर्नामेंट खेल रहे हैं। हॉकी एशिया कप 27 अगस्त से 7 सितंबर के बीच बिहार के राजगीर में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीमों के बीच एशिया कप मैच पर अधिकारी ने कहा, %ब्रॉडबून ने अब तक इस बारे में सरकार से बात नहीं की है। जैसे ही बोर्ड की ओर से बातचीत होगी, टीम इंडिया के एशिया कप में हिस्सा लेने पर फैसला लेंगे। पाकिस्तान हॉकी बोर्ड ने अभी तक टूर्नामेंट में आने या न आने पर कोई भी बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उसने टूर्नामेंट से खुद को अलग भी नहीं किया है, जिससे माना जा रहा है कि टीम खेलने के लिए भारत आएगी। हॉकी इंडिया ने कहा था- सरकार के निर्देश मानेंगे हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह ने कहा था, पाकिस्तान टीम एशिया कप के लिए आएगी या नहीं, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पहलगाम में आतंकी हमला और भारत का ऑपरेशन सिंदूर पिछले महीने ही हुआ। ऐसे में इस वक्त कुछ भी कह पाना



मुश्किल है। हम शांति कायम होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के जो भी निर्देश होंगे, हम उनका पालन करेंगे। हॉकी इंडिया के एक अन्य अधिकारी ने कहा था, अगर सरकार ने पाकिस्तान को एंट्री देने से मना किया तो उनके बिना टूर्नामेंट कराया जाएगा। सबकुछ सरकार के फैसले पर निर्भर है। 2016 में भारत नहीं आई थी पाकिस्तान टीम 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। तब भी पाकिस्तान हॉकी टीम भारत नहीं आई थी। तब पाकिस्तान की जगह मलेशिया को एंट्री देकर टूर्नामेंट कराया गया था। दोनों देशों में तनाव के बाद पाकिस्तान का जूनियर हॉकी

वर्ल्ड कप के लिए भी भारत आना मुश्किल लग रहा था। टूर्नामेंट चेन्नई और मदुरै में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक खेला जाएगा। हालांकि मंत्रालय से आपत्ति नहीं होने के बाद अब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान टीम भारत आ सकती है। वर्ल्ड कप में डायरेक्ट एंट्री दिलाता है एशिया कप नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में अगले साल 14 से 30 अगस्त तक हॉकी वर्ल्ड कप होगा। एशिया कप जीतने वाली टीम को वर्ल्ड कप में डायरेक्ट एंट्री मिलती है। एशिया कप में 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया डिफेंडिंग चैंपियन है। वहीं भारत और पाकिस्तान को अपने-अपने चौथे टाइटल का इंतजार है। हॉकी एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के अलावा जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया, ओमान और चीनी ताहपे भी हिस्सा लेंगी। 4-4 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। दोनों ग्रुप की 2-2 टॉप टीमों के बीच 7 सितंबर को फाइनल होगा। भारत ने ॲपरेशन सिंदूर से किया था हिसाब बराबर कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 3 आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। जिसके बाद भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निकाल दिया। भारत ने 7 मई की देर रात ॲपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया और पहलगाम हमले का बदला लिया। जिसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से भारत पर हमला कर दिया। भारत ने जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों देशों में बॉर्डर पर तनाव चला और 10 मई को सीजफायर हो गया। दोनों ही देश अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।

अब समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं लगेगा चार्ज

आरबीआई का नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा

न्यूज़ क्राइम फाइल

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने लोन लेने वालों को राहत दी है। दरअसल, RBI ने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक का यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति समय से पहले अपने लोन को थोड़ा या पूरा चुकाता है, तो बैंक ये चार्ज वसूलता था। नया नियम सभी बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों समेत रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए अनिवार्य रहेगा। इससे करोड़ों लोन लेने वाले लोगों, खासकर होम लोन और MSE लोन लेने वालों को सीधा फायदा मिलेगा।

RBI के फैसले से किसे फायदा मिलेगा ?

इस फैसले से उन व्यक्तियों को फायदा मिलेगा, जिन्होंने नॉन कॉर्मशियल काम के लिए फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है। भले ही किसी व्यक्ति ने अकेले लोन लिया हो या को-ऑप्लिंग के साथ लोन लिया हो। ऐसे सभी लोन पर कोई भी बैंक या NBFC प्री-पेमेंट चार्ज नहीं वसूल सकेगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने बिजनेस के लिए लोन लिया है या किसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (स्स्थ) ने लोन लिया है, तब भी कॉर्मशियल बैंक प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लगाएंगे। हालांकि, यह



छूट कुछ खास कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं होगी।

किन इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिलेगा

लाभ ?

- स्मॉल फाइनेंस बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- लोकल एरिया बैंक
- टियर-4 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
- NBFC-अपर लेयर
- ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
- 50 लाख तक के लोन पर भी राहत
- अगर किसी व्यक्ति या स्स्थ को ऊपर दिए

गए इंस्टीट्यूशंस से 50 लाख तक का लोन मिला है, तो उस पर भी प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा। इसमें टियर-3 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, स्टेट और सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक और NBFC-अपर लेयर शामिल हैं।

RBI ने यह फैसला क्यों लिया ?

RBI ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई कि कई रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस प्री-पेमेंट चार्ज को लेकर अलग-अलग पांचलिंगी अपना रही थीं। इससे ग्राहकों में भ्रम और विवाद की स्थिति बन रही थी। इसके अलावा

कुछ इंस्टीट्यूशंस लोन एग्रीमेंट में ऐसे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज शामिल कर रहे थे। जिससे ग्राहक कम ब्याज दर वाले ऑप्शन पर स्विच न कर सकें। RBI ने कहा कि यह राहत लोन चुकाने के सोर्स पर निर्भर नहीं होगी। यानी चाहे लोन का पार्ट पेमेंट हो या पूरा लोन पेमेंट हो और फंड का सोर्स कोई भी हो, अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही किसी भी तरह का लॉक-इन परियार्थ नहीं होगा।

फिक्स्ड टर्म लोन पर क्या फायदा होगा ?

नए नियमों के मुताबिक, फिक्स्ड टर्म लोन पर अगर प्री-पेमेंट चार्ज लागाया भी जाता है, तो वह सिफ़र प्री-पे की गई राशि पर बेस्ड होना चाहिए। वहीं, ओवरड्राफ़ या कैश क्रेडिट के मामलों में नियम थोड़ा अलग है। अगर लोन लेने वाला समय से पहले रिन्यूएबल न करने की सूचना देता है और तय तारीख पर लोन खत्म कर देता है, तो कोई प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लगाया जाएगा।

की-फैक्टर्स स्टेटमेंट में पूरी डिटेल्स जरूरी

RBI ने यह भी निर्देश दिया है कि प्री-पेमेंट चार्ज से जुड़े सभी नियमों की जानकारी लोन एक्सेप्टेंस लेटर, कॉन्ट्रैक्ट और की-फैक्टर्स स्टेटमेंट (स्स्टर्स) में दी जानी चाहिए। अगर च्स्सर्स में कोई चार्ज पहले से मेंशन नहीं है, तो बाद में उसे वसूल नहीं किया जा सकता।



पुलिसकर्मी ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारी

इंदौर में दोस्त से कष्ट था- पत्नी कॉल नहीं उठा रही, अब मेरी लाश मिलेगी

न्यूज क्राइम फाइल

इंदौर में एक आरक्षक ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मामला शुक्रवार तड़के करीब 5 बजे का है। 28 वर्षीय अनुराग भासोर ने द्वारिकापुरी इलाके में दिवंगिय मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के एक फ्लैट में अपनी जान दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना के समय अनुराग के साथ सिपाही रोहित भी मौजूद था। उसने बताया कि अनुराग ड्यूटी के दौरान आ रहे फोन कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा था। शुरुआती जांच में पत्नी से विवाद की बात सामने आई है। अनुराग ने डेढ़ साल पहले लव मैरिज की थी। पत्नी रानू धार के माड़व की रहने वाली है। 7 दिन से मायके में ही है। अनुराग, अलीराजपुर का निवासी था। द्वारिकापुरी थाने से पहले वह सरफा थाने में था।

बोला- वह मेरी लाश के आसपास भी नहीं भटके



अनुराग भासोर, मृतक

अनुराग ने रात में अपने दोस्त विकास क्षुनिया से मोबाइल पर बात की थी। उसने कहा था- पत्नी फोन नहीं उठा रही है। मैसेज देखने के बाद भी रिप्लाई नहीं किया। उसे कह देना कि अब मेरी लाश देखने को मिलेगी। वह लाश के आसपास भी नहीं भटके। संभवतः अनुराग की यह अखिरी बातचीत थी। पुलिस इस मामले में दोस्त के बयान लेगी।

पत्नी को 7 दिन पहले करंट लगा था। परिवार में बड़ा भाई अविनाश और छोटा भाई देवेंद्र हैं। अनुराग मंझला था। पिता वेटरिनरी से लौटे थे। उन्हें रात में कोई आवाज नहीं आई। श्याम पंडिताई का काम करते हैं।

डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं। अनुराग की बुआ के बेटे राजेंद्र ने बताया कि उसे पुलिस विभाग में 10 साल हो गए थे। अनुराग की पत्नी के भाई को 7 दिन पहले करंट लगा था। अरविंदो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। परिजन के मुताबिक, सर्वांका से द्वारकापुरी थाने में ट्रांसफर के बाद अनुराग का ड्यूटी शेड्यूल बढ़ गया था। वह अपने घर-अस्पताल नहीं जा पा रहा था। पत्नी अरविंदो अस्पताल में मायके पक्ष के लोगों के साथ ही थी। इसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था।

आईडीए की बिल्डिंग, फ्लैट पुलिस विभाग को अलॉट

जिस बिल्डिंग में अनुराग ने खुदकुशी की, वह इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी (आईडीए) की है। यहां अक्सर नशाखोरी और विवाद सामने आते हैं, इसलिए पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है। अनुराग भी ड्यूटी पर तैनात था। जिस फ्लैट में घटना हुई, वह पुलिस विभाग को अलॉट है। पड़ोसी श्याम लाल बामनिया ने बताया कि वे रात 11 बजे शादी से लौटे थे। उन्हें रात में कोई आवाज नहीं आई। श्याम पंडिताई का काम करते हैं।

मध्यप्रदेश में शॉपिंग मॉल, बाजार-कारखानों में रात में काम कर सकेंगी महिलाएं

एमपी सरकार ने दी सर्वत्र मंजूरी; सुरक्षा की व्यवस्था नियोक्ता को करनी होगी

न्यूज क्राइम फाइल

मध्यप्रदेश में शॉपिंग मॉल, बाजार और कारखानों, प्रोडक्शन यूनिट्स में अब महिलाएं भी दिन-रात काम कर सकेंगी। राज्य सरकार ने शर्तों के साथ महिलाओं के रात में काम करने की सहमति दे दी है। इसके लिए महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन नियोक्ता (एम्प्लॉयर) एजेंसी को करना होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से महिला कर्मचारियों को आर्थिक प्रगति मिलेगी। वहीं कारोबारियों और उद्योगपतियों को अपने यूनिट्स का कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसका असर प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने वाला होगा।

शॉप में 10 या ज्यादा महिलाएं होनी चाहिए नियुक्त

दुकान और स्थापना अधिनियम, 1958 में किए गए संशोधन के आधार पर श्रम विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक महिलाएं काम कर सकेंगी। जहां महिलाएं रात में काम करेंगी, उस शॉप में



शॉप में कम से कम 10 या अधिक महिलाएं होनी चाहिए। कारखानों में एक-तिहाई कर्मचारी होना अनिवार्य

कारखानों के मामले में भी इसी तरह की व्यवस्था रहेगी। कारखाना अधिनियम की शक्तियों का उपयोग करते हुए 26 जून 2016 के नियमों को समाप्त कर यह तय किया है कि

महिलाएं चाहें तो रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी कारखाने या प्रोडक्शन यूनिट में काम कर सकती हैं। कारखानों और प्रोडक्शन यूनिट्स में महिलाओं के रात्रि शिफ्ट में काम करने के दौरान सुपरवाइजर, शिफ्ट इन-चार्ज, फोरमैन या अन्य सुपरवाइजर कर्मचारियों में कम से कम एक तिहाई महिला कर्मचारी होना चाहिए।

फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉर्मस ने कहा- सुरक्षा जरूरी

फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉर्मस भोपाल के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश अग्रवाल ने सरकार के फैसले को लेकर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगर वे रात में ड्यूटी करेंगी, तो उनके अनुसार पूरी व्यवस्था होना चाहिए। यदि रात में उन्हें छोड़ा जाना है, तो उन्हें घर तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। इससे कारखानों, प्रोडक्शन यूनिट्स और दुकानों के संचालकों को तो लाभ होगा ही, साथ ही महिलाओं और उनके परिवारों को भी आर्थिक व सामाजिक संबल मिलेगा।



दो हजार लोगों की कॉल डिटेल खंगाली, जेल में बंद बॉयफ्रेंड के दोस्त ही हत्यारे निकले

खंडवा में सेक्स वर्कर से गैंगरेप, फिर की थी हत्या...



न्यूज़ क्राइम फाइल

खंडवा में 40 वर्षीय महिला की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का शव 21 जून को नग्न अवस्था में कोतवाली क्षेत्र में एक सुनसान जगह मिला था। उसके सिर को पथरों से कुचला गया था। तेरहवीं के दिन पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने में सफलता पाई। एसपी

मनोज कुमार राय ने बताया कि मृतका अनैतिक गतिविधियों में लिस थी और शराब की आदी थी। पुलिस ने दो हजार लोगों की कॉल डिटेल खंगालकर करीब 200 लोगों से पूछताछ की। एक नंबर की लोकेशन महाराष्ट्र के नासिक में मिली, जो घटना वाले दिन घटनास्थल के आसपास एक्टिव था।

आरोपी नशे में थे, जबरन संबंध बनाए गिरफ्तार आरोपियों के नाम प्रिंस पिता

विनोद शर्मा (19) और दीवाल उर्फ राधे पिता जगदीश कुचबंदिया (25), दोनों निवासी रामनगर हैं। 20 जून को दोनों आरोपी महिला को स्कूटी से चीराखदान मल्टी से उठाकर भंडारिया रोड स्थित सुनसान जगह ले गए। वहाँ दो बीयर और एक क्राटर शराब पी। जब महिला ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया, तो परिवार को बताने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म किया।

जिस बच्चे को पिता ने फेंका था, उसकी मौतः पत्नी के घूंघट न करने से नाराज होकर सड़क पर पटका था, अब हत्या का केस चलेगा

न्यूज़ क्राइम फाइल

उज्जैन के बड़नगर में 29 जून को पत्नी के घूंघट न करने से नाराज शख्स ने अपने तीन साल के बेटे को सड़क पर बेरहमी से पटक दिया था। सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आने के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहाँ बुधवार रात इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 45 बढ़ाते हुए हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, करीब पांच दिन पहले उमरिया गांव निवासी आजाद शाह और उसकी पत्नी मुस्कान का रिश्तेदारों से विवाद हो गया था। 29 जून की शाम दोनों बड़नगर थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। इसके बाद दोनों पति-पत्नी वापस अपने घर लौट रहे थे। बारिश होने लगी तो आजाद ने बेटे तनवीर को अपनी गोद में ले लिया। चौपाटी पर पहुंचते ही सामने से गांव के कुछ लोग आते दिखे। इस पर आजाद ने



मुस्कान से सिर पर घूंघट डालने को कहा। इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर आजाद ने तनवीर को सड़क पर पटक दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने आजाद को पकड़कर पुलिस को फोन किया।

जेल में है आरोपी पिता

3 साल के तनवीर को बड़नगर अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफर किया गया। जहाँ से उसे परिजन एक निजी अस्पताल में ले गए थे। उधर, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 296 एवं अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर आजाद को कोर्ट में पेश किया था। जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया था।

हत्या की धारा में चलेगा केस

बड़नगर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया कि मुस्कान ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि आजाद ने बच्चे को जानबूझकर सड़क पर पटका था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। घटना के तुरंत बाद ढाबा संचालक पीयूष मोरवाल ने आरोपी को पकड़ लिया था। फिलहाल आजाद शाह जेल में है। बच्चे की मौत के बाद अब उसके खिलाफ धारा 45 बढ़ाते हुए हत्या का मामला दर्ज किया गया है।



विपिन फिर बोला- सोनम ने राजा की बलि दी

कहा- हत्या के बाद इंदौर आकर राज से शादी की होगी, दूसरा मंगलसूत्र उसी का

न्यूज़ क्राइम फाइल

इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में उसके भाई विपिन ने गुरुवार को बलि देने की बात दोहराई। विपिन ने कहा- सोनम ने शादी के पहले अपनी मां से कहा था कि उसकी पसंद की शादी नहीं हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और इस तरह सोनम ने शादी के बाद राजा को मारकर उसकी बलि देकर अपनी इच्छा तो पूरी कर ली है। विपिन ने कहा, राजा को मारने के बाद जब सोनम इंदौर आई तो उसने राज से शादी कर ली होगी, इसलिए दूसरा मंगलसूत्र उसी का होगा। दो में से एक मंगलसूत्र हमारा दिया हुआ है। जबकि दूसरा हमने नहीं दिया। एक चेन और पायजेब भी बरामद की गई है, वो भी हमारी नहीं है। बता दें कि बुधवार को राजा की मौसेरी बहन सृष्टि के खिलाफ असम में एफआईआर दर्ज करने की जानकारी आई थी। ये एफआईआर इंस्टाग्राम वीडियो में नरबलि की बात कहकर छवि बिगाड़ने के आरोप पर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में विपिन ने कहा- 15 दिन पहले हमें असम पुलिस का नोटिस मिला था। इसमें कहा था कि नरबलि के सबूत हैं तो दें वरना माफी मांगें। इस पर हमने माफी मांग ली थी। एफआईआर जैसी कोई बात नहीं है। मामले में कामाख्या मर्दिर के पुजारी सरू डोलोई हिमाद्रि का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि जब भी कामाख्या मर्दिर के आसपास कोई हत्या का मामला होता है तो मंदिर में मानव बलि का मुद्दा उठाया जाता



है। इस तरह के आरोपों से यहां के लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। पुजारी का कहना है कि राजा की नरबलि का दावा धार्मिक भावनाएं भड़काने और क्षेत्रीय तनाव पैदा करने वाला है।

सृष्टि ने लेटर मिलने के बाद माफी मांगी थी

विपिन ने गुरुवार को बताया कि सृष्टि को असम सरकार की ओर से करीब 15 दिन पहले पत्र आया था। उसमें कहा गया था कि नरबलि को लेकर आपके पास कोई सबूत हो तो बता दीजिए। वरना अपने बयान पर माफी मांगिए। पत्र में कहा गया था कि आप केस को डायर्वर्ट कर रहे हों और धर्म को बीच में ला रहे हों। इसके बाद सृष्टि ने माफी मांग ली थी। हमने

आशंका जाहिर की थी। इसके बाद हमने माफी मांग ली है। वहां अब बयान के लिए नहीं जाना है।

मां और भाई ने पहले भी जताई थी बलि की आशंका

राजा की मां उमा और भाई विपिन रघुवंशी ने भी 11 जून को नरबलि की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि आखिर सोनम राजा को लेकर शिलौना क्यों जाना चाहती थी? राजा की मां ने दावा किया था कि बेटे राजा पर तंत्र क्रिया की गई होगी। सोनम ने मेरे बेटे की नरबलि देंदी। हम सब पर भी सोनम ने वशीकरण किया था। जैसा वह लोग बोल रहे थे, हम वैसे ही चल रहे थे। अब हमें इसका एहसास हो रहा है। परिजन ने आशंका जताई थी कि हो सकता है

सोनम ने मन में नरबलि देने के लिए मनोकामना की हो क्योंकि कामाख्या देवी में पूजा करने के बाद आरोपियों ने राजा के गले पर वार किया था। जिस दिन राजा की हत्या हुई, उस दिन ग्यारह थी। राजा की मां ने दावा किया है कि इस हत्याकांड के पीछे 15 लोग हो सकते हैं।

बयान और वीडियो के बाद ट्रोल हो चुकी है सृष्टि

सृष्टि सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर है। वह अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिए विज्ञापन भी करती है। इसके चलते उसके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स भी हैं। राजा के मेघालय में लापता होने के बाद से ही सृष्टि ने सोशल मीडिया पर कैपेन शुरू किया था। वह लगातार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी। राजा की हत्या और सोनम के पकड़े जाने के बाद भी सृष्टि के कई वीडियो वायरल हुए। इसके चलते उसे काफी ट्रोल किया गया। यहां उसका जमकर विरोध हुआ। कहा गया कि सृष्टि यह सब वायरल होने के लिए कर रही है। हालांकि सृष्टि के समर्थन में भी कई सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर आए थे।

सृष्टि बोली- भावुक होकर दिया बयान

राजा के लापता होने से लेकर शब्द बरामद होने तक सृष्टि सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रही थी और मदद की गुहार लगाती रही। इसी दौरान उसने एक वीडियो में नरबलि जैसा बयान दिया, जो अब विवाद में आ गया है।

कलेक्टर की शिकायत करने भाजपा पदाधिकारियों के साथ पहुंचे बिल्डर

प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर से बोले- टीकमगढ़ में अवैध कॉलोनियों पर तत्काल कार्रवाई बंद करा दे

न्यूज़ क्राइम फाइल



टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रेत्रिय ने जिले में अवैध कॉलोनाइजर्स और भू-माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। कलेक्टर की मुहिम के खिलाफ टीकमगढ़ जिले के बिल्डर, कॉलोनाइजर, भाजपा पदाधिकारियों के साथ भोपाल पहुंचे। भाजपा जिला अध्यक्ष सरोज राजपूत, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राहुल तिवारी, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे (रानू), मनोज देवलिया ने करीब दो दर्जन कॉलोनाइजर्स के साथ टीकमगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर से मुलाकात की।

मंत्री से बोले- कलेक्टर से कहिए कार्रवाई रोक दें

जतारा जनपद पंचायत के अध्यक्ष

प्रतिपक्ष अभिषेक खरे रानू ने मंत्री से कहा- करीब 10 हजार लोगों ने प्लॉट लिए हैं। गरीब लोग 10 साल से मकान बनाकर रह रहे हैं। जो चल रहा है, उसको तत्काल ब्रेक किया जाए। बीजेपी नेता मनोज देवलिया ने कहा- सरकारी सिस्टम में ऐसी दिक्कत हैं कि कागजी कार्रवाई में सालों लग जाते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन में डेढ़ साल लग जाते हैं। टीएंडसीपी के बाद रेरा में मामला जाता है। ऐसे तीन-चार साल लग जाते हैं। एक सिंगल विंडो सिस्टम जिले में लागू कर दिया जाए।

हम सारे पेपर वहां जमा कर दें। वो जांच करके कॉलोनी को स्वीकृत कर दें। हम पूरी फीस जमा कर दें। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। इस प्रक्रिया में बहुत टाइम लगता है। 20-20 लाख रुपए लग जाते हैं। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई रोकने कलेक्टर से

बात करुंगी मंत्री कृष्णा गौर ने अपने बंगले पर पहुंचे लोगों से कहा- मेरे समक्ष समस्या आपके जनप्रतिनिधियों ने रखी है। उसमें प्रमुख रूप से यही बात है कि जिस तरह से कलेक्टर की कार्रवाई पूरे जिले में अवैध रूप से बनी कॉलोनियों पर चल रही है।

आप सबकी ऐसी मंशा है कि उस कार्रवाई को अभी रोका जाए। जैसी कलेक्टर की मंशा है कि अवैध कॉलोनियों को बैध किया जाए। और लोगों को राहत दी जाए। क्योंकि, अवैध कॉलोनियां बहुत सारी मुश्किलों का कारण तो बनती ही हैं। मप्र में सरकार भी यही चाहती है कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियां नहीं बननी चाहिए। क्योंकि, अवैध कॉलोनियों के कारण जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और कहीं न कहीं फिर वो सरकार और शासन की जिम्मेदारी हो जाती है।



इंदौर मेट्रो का एक महीना- टाइम बदला, किराया बढ़ा

25 हजार तक यात्रियों ने एक दिन में किया था सफर, अब 500 भी नहीं आ रहे

न्यूज़ क्राइम फाइल

इंदौर मेट्रो के 5.9 किमी के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर कमर्शियल रन को एक महीना हो गया है। इस अवधि में यात्रियों की संख्या में भी गिरावट आने लगी है। इंदौर मेट्रो के शुरुआती दिन में जहां प्रतिदिन यात्रियों की संख्या 25 हजार से अधिक पहुंची थी। अब रोजाना 500 से भी कम लोग सफर करने पहुंच रहे हैं। हालांकि, बीकंड पर शनिवार और रविवार को ही यात्री संख्या 1 हजार से ज्यादा पहुंच पाती है। सप्ताह की बात करें तो शुरुआत में 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया था। वहीं, यह हर सप्ताह का आंकड़ा बमुश्किल 10 हजार को पार कर पा रहा है। घटते यात्रियों के चलते मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंदौर मेट्रो की संचालन व्यवस्था में भी बदलाव किया है। यात्रियों की संख्या और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों मेट्रो की नई समय-सारणी और किराए की नई दरें घोषित की गई थीं। यह बदलाव 23 जून 2025 से प्रभाव में आ गया था। अब इंदौर मेट्रो का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। वहीं, हर 1 घंटे में मेट्रो चलाई जाती है। पहले सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मेट्रो संचालन किया जा रहा था, जबकि हर 15 मिनट में मेट्रो ट्रेन



संचालित हो रही थी।

शुरुआत में 1.5 लाख से ज्यादा यात्री मिले

इंदौर मेट्रो का औपचारिक शुरुआत 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से किया था। 31 मई के बाद से 21 जून तक इंदौर

मेट्रो में कुल 1 लाख 95 हजार 303 यात्रियों ने इसमें सफर किया। यात्रियों को जहां पहला सप्ताह फ्री राइड मिली थी तो उसके बाद किराए में रियायत मिलती रही। अभी तक यात्रियों को किराए में 75 और 50 प्रतिशत रियायत मिल चुकी है। उसके बाद अब मेट्रो में यात्री टिकट

राशि पर 25 प्रतिशत रियायत के साथ सफर कर रहे हैं। पिछले सप्ताह की बात करें तो इंदौर मेट्रो में 11 हजार 579 यात्रियों ने सफर किया। 22 जून को 5 हजार 273, 23 जून को 690, 24 जून को 501, 25 जून को 717, 26 जून को 488, 27 जून को 503, 28 जून को 1 हजार 289 और 29 जून को 4 हजार 118 यात्रियों ने सफर किया। बता दें कि 28 जून को शनिवार और 29 जून को रविवार था।

समय पर नहीं चल रही मेट्रो

इंदौर मेट्रो का वर्तमान समय (शनिवार और रविवार को छोड़कर) सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। इस दौरान मेट्रो का संचालन हर 1 घंटे में होता है। लेकिन, मेट्रो अपने तय समय से 15 मिनट तक लेट चल रही है।

दिल्ली में करते हैं सबसे ज्यादा यात्री सफर

देश के बड़े शहरों में मेट्रो संचालन को लेकर जो स्थिति है उसके मुताबिक दिल्ली मेट्रो में प्रतिदिन यात्रियों की संख्या औसतन 60 लाख से अधिक है। मुंबई मेट्रो में प्रतिदिन यात्रियों की संख्या 2025 में लगभग 3 लाख है। जयपुर मेट्रो में प्रतिदिन 50,000 से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। बंगलुरु मेट्रो में प्रतिदिन यात्रियों की संख्या लगभग 8.5 से 9 लाख हैं और हैदराबाद मेट्रो में प्रतिदिन यात्रियों की संख्या 5 लाख से अधिक है।

एमपी में एक अक्टूबर से महंगा होगा टाइगर रिजर्व पर्यटन

दस प्रतिशत बढ़ जाएगी एंट्री फीस, विदेशियों को दुकानी होगी दोगुनी राशि

न्यूज़ क्राइम फाइल

एमपी में नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में घूमना एक अक्टूबर से महंगा हो जाएगा। सरकार ने मौजूदा प्रवेश टिकट फीस में दस फीसदी की बढ़ातरी करने का फैसला किया है। विदेशी पर्यटकों को भारतीय पर्यटकों की बजाय दोगुनी टिकट फीस देनी होगी। प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों एवं बाघ अभ्यारण्यों में भ्रमण के लिए प्रवेश टिकट की बुकिंग एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होती है। प्रदेश के ज्यादातर टाइगर रिजर्व में सोमवार से शुक्रवार तक छह लोगों के प्रवेश पर 2400 रुपए और शनिवार-रविवार को 3000 रुपए प्रवेश शुल्क लिया जाता है। एक अक्टूबर से इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद पर्यटकों को क्रमशः 240 और 300 रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगे। इसमें जिसी का किराया शामिल नहीं है। जिसी के लिए पर्यटकों को अलग-अलग पार्क में 2000 से 3500 रुपए तक अतिरिक्त देने पड़ते हैं। वहीं विदेशी पर्यटकों को दो गुना शुल्क चुकाना पड़ता है।



रिजर्व को काफी पसंद कर रहे हैं। इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अकेले बांधवगढ़ की बात करें, तो पिछले 5 वर्ष में भारतीय पर्यटकों की संख्या 7 लाख 38 हजार 637 और विदेशी पर्यटकों की संख्या 85 हजार 742 रही।

टिकट के दाम बढ़ाने ऐसे हुआ था फैसला

प्रदेश सरकार ने 22 अक्टूबर 2024 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें मैहर जिले के मुकुंदपुर वाइट टाइगर रिजर्व सफारी, भोपाल के बन विहार राष्ट्रीय उद्यान और इंदौर के रालामंडल अभ्यारण्य के प्रवेश शुल्क में 5 रुपए की बढ़ातरी की गई थी। इसी अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया था कि प्रदेश के सभी संरक्षित क्षेत्रों नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के प्रवेश शुल्क में हर तीन साल में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह नीति 2025-26 से प्रभावी हो रही है। इसलिए एक अक्टूबर से सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में घूमना महंगा हो जाएगा।

तीन माह बंद रहेंगे पार्क

मानसून के कारण प्रदेश के सभी संरक्षित क्षेत्रों में तीन माह जुलाई से सितंबर पर्यटन बंद रहेंगे। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह ब्रीडिंग सीजन है और दूसरा बारिश के कारण नदी-नालों में काफी पानी रहता है। बारिश के कारण जंगल के रास्ते भी खराब हो जाते हैं। ऐसे में पर्यटन करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक सभी पार्क बंद कर दिए जाते हैं। यानी 1 अक्टूबर को इन पार्कों में फिर से पर्यटन शुरू होगा। विदेशी पर्यटक मध्य प्रदेश के टाइगर



दिल्ली- पुराने वाहनों को नो-फ्यूल आदेश वापस लेने की तैयारी

मंत्री ने कहा- पॉल्यूशन देखकर रोक लगे; 1 जुलाई से लागू होना था

संदीप कुमार सिंह

दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता आयोग को लेटर लिखकर पुराने वाहनों पर ईंधन भरवाने की रोक को फिलहाल रोकने की अपील की है। ये जानकारी गुरुवार को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी। उन्होंने कहा कि जब तक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचानने वाला सिस्टम पूरे एनसीआर में पूरी तरह नहीं लग जाता, तब तक इस नियम को लागू न किया जाए। सरकार वायु प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठा रही हैं और इसका असर जल्द दिखेगा। दरअसल, CAQM ने अप्रैल में आदेश दिया था कि 1 जुलाई से पुराने वाहनों में ईंधन नहीं डाला जाएगा, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। ये नियम दिल्ली के साथ-साथ बाहर से आए पुराने वाहनों पर भी लागू हैं। ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचानने वाला सिस्टम पूरे एनसीआर में अभी लागू नहीं हुआ है। जहां अभी लगाया गया है, वहां ठीक से काम नहीं कर रहा। कैमरे, सेंसर्स और स्पीकर्स में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में इस नियम को लागू करना उचित नहीं है।

दिल्ली की हवा हर रोज 38 सिगरेट पीने

जितनी

नवंबर 2013 में दिल्ली में औसतन प्रदूषण का लेवल 287 AQI था। नवंबर 2024 में प्रदूषण का लेवल औसतन 500 AQI से ऊपर पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2013 में एक व्यक्ति औसतन 10 सिगरेट जितना धुआं



मंत्री सिरसा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 अहम बातें

दिल्ली के पड़ोसी शहरों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में अभी तक हक्क कैमरे नहीं लगे हैं। इससे वाहन मालिक दिल्ली से बाहर जाकर ईंधन भरवा सकते हैं। ऐसे में गैरकानूनी ईंधन बाजार बनने का खतरा बढ़ सकता है। कई वाहनों की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स में समस्याएं हैं, जिससे NPR उन्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहा। दिल्ली सरकार ने मार्च में नए नियम की घोषणा की थी एक मार्च को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि जुलाई से 15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। ऐसे वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा।

प्रदूषण के जरिए अपने अंदर ले रहा था। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 38 सिगरेट तक पहुंचा। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद पॉल्यूटेंट्स भी हमारे फेफड़ों में समा जाते हैं। ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर सकते हैं और खांसी या आंखों में खुजली पैदा कर सकते हैं।

इससे कई रेस्पिरेटरी और लंगस से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। कई बार तो यह कैंसर की बजह भी बन सकता है। अब लगातार नई स्टडीज में सामने आ रहा है कि इससे ब्रेन की फंक्शनिंग भी प्रभावित होती है। लैंसेट न्यूरोलॉजी जर्नल में पब्लिश ग्लोबल

स्टडी के मुताबिक वायु प्रदूषण सबराकनॉइड हैमरेज (Subarachnoid Haemorrhage) यानी SAH की बड़ी बजह है। इसमें पता चला है कि साल 2021 में सबराकनॉइड हैमरेज के कारण होने वाली लगभग 14 लाख मौतों और विकलांगता के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। यह स्पोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। एयर क्लालिटी इंडेक्स का क्या मतलब है? एयर क्लालिटी इंडेक्स (AQI) एक तरह का टूल है, जो यह मापता है कि हवा कितनी साफ और स्वच्छ है। इसकी मदद से हम इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें मौजूद एयर पॉल्यूटेंट्स से हमारी सेहत को क्या नुकसान हो सकते हैं। AQI मुख्य रूप से 5 सामान्य एयर पॉल्यूटेंट्स के कॉन्सन्ट्रेशन को मापता है। इसमें ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकल पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल हैं। आपने AQI को अपने मोबाइल फोन पर या खबरों में आपतौर पर 80, 102, 124, 250 इन संख्याओं में देखा होगा। इन अंकों का क्या मतलब होता है, ग्राफिक में देखिए। दिल्ली में गाड़ियों से 12% प्रदूषण बढ़ा 2023-24 के इकोनॉमिकल सर्वे के मुताबिक, दिल्ली में करीब 80 लाख गाड़ियां हैं। इनसे सबसे छोटे प्रदूषित कण PM 2.5 निकलते हैं। दिल्ली के प्रदूषण में 47% PM 2.5 इन्हीं वाहनों से निकलता है। यह वाहन न सिर्फ हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं बल्कि यह धूल से होने वाले प्रदूषण की भी बजह बनते हैं। दिल्ली में 12% प्रदूषण इन्हीं गाड़ियों से बढ़ा है।

केजरीवाल का ऐलान- बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी आप



न्यूज़ क्राइम फाइल

आम आदमी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अहमदाबाद में कहा, I.N.D.I.A. गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। अब हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। केजरीवाल गुजरात के दो दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात

के विसावदर उपचुनाव में हमने कांग्रेस से अलग लड़कर तीन गुना ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा, यह जनता का सीधा संदेश है कि अब विकल्प आम आदमी पार्टी है। आगे गुजरात में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। दिल्ली में हार पर कहा कि ऊपर-नीचे होता रहेगा। पंजाब में हमारी सरकार दोबारा बनेगी। भाजपा की सरकार ने गुजरात को बर्बाद कर दिया है। सूरत समेत कई शहर पानी में डूबे हुए हैं। किसान, युवा और व्यापारी समेत सभी वर्ग परेशान हैं। इसके बाद भी बीजेपी गुजरात में जीतती आ रही है, क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं था। कांग्रेस पार्टी को बीजेपी को जीत दिलाने के लिए ठेका दिया जाता है। अब आम आदमी पार्टी आ गई है। आम आदमी पार्टी को लोग एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। विसावदर में जिस तरह से लोगों ने वोट दिया। ये माहौल, ये गुस्सा पूरे गुजरात के लोगों के अंदर है। मैंने कई जगह लोगों से बात की। लोगों में इसी तरह का गुस्सा है। यहीं गुस्सा विसावदर में देखने को मिला। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था कि इनके बोट काटो। कांग्रेस ने ठीक से काम नहीं किया। बीजेपी से कांग्रेस वालों को खूब डांट पड़ी। इंडिया गर्भबंधन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा- वह अलायंस लोकसभा के लिए था। अब हमारी तरफ से कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ दो साल दीजिए, ये हवन है, इसमें आहुति दीजिए पार्टी की सदस्यता के लिए केजरीवाल ने 9512040404 नंबर जारी कर कहा कि इस पर मिस्ट कॉल देकर आम आदमी पार्टी से जुड़िए। उन्होंने आगे कहा कि विसावदर उपचुनाव में जनता ने हम पर भरोसा किया है। अगर गुजरात का विकास करना है तो युवाओं को हमारे साथ जुड़ा चाहिए।